चीनी उद्योग को पैकेज जल्द

चीनी उद्योग को राहत पैकेज देने के बारे में फैसला 25 दिसंबर को क्रिसमस से पहले कर सकती है। इस पैकेज में 7200 करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त कर्ज होगा। जिससे चीनी मिलें किसानों को गन्ना खरीद का बकाया भुगतान कर सकें। मिलों को पिछले सीजन में खरीदे गन्ने का हजारों करोड़ रुपये का भुगतान बाकी है।

प्रस्ताव ◆ चीनी मिलों को 7200 करोड़ का ब्याज मुक्त कर्ज देने की तैयारी

चीनी उद्योग के राहत पैकेज पर फैसला एक पखवाड़े में

बाजार में चीनी के दाम कम होने से उद्योग पर वित्तीय दबाव

बिजनेस भास्कर ◆ नई दिल्ली

चीनी उद्योग को राहत पैकेज देने के बारे में फैसला 25 दिसंबर को क्रिसमस से पहले कर सकती है। इस पैकेज में 7200 करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त कर्ज होगा। जिससे चीनी मिलें किसानों को गन्ना खरीद का बकाया भुगतान कर सकें। मिलों को पिछले सीजन में खरीदे गन्ने का हजारों करोड़ रुपये का भुगतान बाकी है।

इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन (इस्मा) की 79वीं सालाना बैठक के मौके पर खाद्य एवं उपभोक्ता मामले राज्य मंत्री प्रो. के वी थॉमस ने कहा कि चीनी के दाम लागत से कम होने के कारण, चीनी उद्योग के हुए घाटे की भरपाई के लिए केंद्र सरकार जल्द ही राहत पैकेज उपलब्ध करायेगी। इसके लिए मंत्रालय नोट तैयार कर रहा है, जिस पर चालू महीने में ही फैसला हो सकता है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा गठित मंत्रियों के समूह (जीओएम) ने गन्ना किसानों के बकाये का भुगतान करने के लिए चीनी मिलों को 7,200 करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने की सिफारिश की है। चीनी मिलों को मिलने वाले ऋण पर जो 12 प्रतिशत का ब्याज लगेगा, उसमें से सात प्रतिशत ब्याज का भुगतान शुगर डेवलपमेंट फंड (एसडीएफ) से और पांच प्रतिशत का भुगतान केंद्र सरकार की तरफ से किया जायेगा।

उन्होंने कहा कि चीनी की कीमतों में स्थिरता रखने के लिए सरकार कीमत स्थिरता फंड बनाने पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार चीनी उद्योग को पहले ही आंशिक रूप से डिकंट्रोल कर चुकी है। इसके तहत लेवी चीनी की बाध्यता समाप्त कर चुकी है जिससे उद्योग को सालाना करीब 3,000 करोड़ रुपये का फायदा हुआ है। चीनी उद्योग को हुए घाटे तथा पूंजी प्रवाह के साथ ही किसानों के बकाया भुगतान में हो रही देरी पर चिंता व्यक्त करते हुए थॉमस ने कहा कि चीनी मिलों को अब अपने उत्पादों में विविधता लानी होगी। इस मामले में खाद्य मंत्रालय ने हाल ही में एक रिपोर्ट सौंपी है जिसमें गन्ने और चीनी के बेहतर उत्पादन के तौर-तरीकों पर विचार किया गया है। इन सिफारिशों के क्रियान्वयन से निश्चित रूप से गन्ना उत्पादकों और चीनी उद्योग को फायदा होगा।

चीनी के एक्स-फैक्ट्री दाम उत्तर प्रदेश में 2,900 से 3,050 रुपये प्रति क्विंटल चल रहे हैं जबकि मिलों को लागत करीब 3,400 से 3,600 रुपये प्रति क्विंटल की आती है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में पेराई सीजन 2012-13 का भी चीनी मिलों पर अभी करीब 2,300 रुपये बकाया बचा हुआ है।

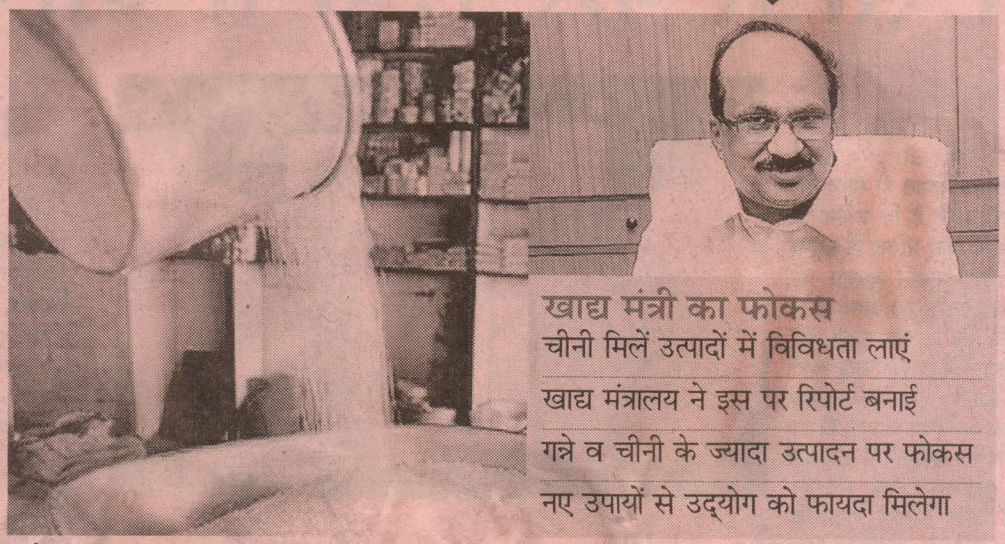

खाद्य मंत्री का फोकस

चीनी मिलें उत्पादों में विविधता लाएं

खाद्य मंत्रालय ने इस पर रिपोर्ट बनाई

गन्ने व चीनी के ज्यादा उत्पादन पर फोकस

नए उपायों से उद्योग को फायदा मिलेगा

Business Bhaskar

12/12/13